प्रश्न : संविधानवाद की अवधारणा और इसकी प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

प्रस्तावना

साधारण शब्दों में, संविधानवाद वह राजनीतिक दर्शन है जो 'सीमित शासन' (Limited Government) और 'विधि के शासन' (Rule of Law) पर आधारित है। यह इस विचार का समर्थन करता है कि सरकार की शक्तियाँ असीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होनी चाहिए।

प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी **चार्ल्स फ्रेडरिक (Carl J. Friedrich)** ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि *"संविधानवाद का अर्थ केवल शक्तियों का विभाजन और उन पर प्रभावी नियंत्रण की एक पद्धति है।"* यदि किसी देश में संविधान तो है, लेकिन वहां सरकार की शक्तियां असीमित हैं (जैसे तानाशाही व्यवस्था में), तो वहां 'संविधान' तो हो सकता है, परंतु 'संविधानवाद' का अभाव माना जाएगा।

संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएँ

संविधानवाद की प्रकृति को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का विश्लेषण अनिवार्य है:

1. विधि का शासन (Rule of Law)

संविधानवाद का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ 'विधि का शासन' है। इसका अर्थ है कि शासन व्यक्तियों की सनक या मर्जी से नहीं, बल्कि स्थापित कानूनों के माध्यम से चलाया जाएगा।

- **ए.वी. डायसी (A.V. Dicey)** के सिद्धांतों के अनुसार, कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि शासक स्वयं भी उसी कानून के अधीन हैं जिसे वे लागू करते हैं।

2. सीमित और उत्तरदायी सरकार (Limited and Accountable Government)

संविधानवाद का मूल उद्देश्य राजनीतिक निरंकुशता को रोकना है। यह सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक अंकुश लगाता है।

- **के.सी. व्हेयर (K.C. Wheare)** का तर्क है कि संविधानवाद का अर्थ ही सरकार पर नियंत्रण की एक प्रणाली है। इसमें शासन की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं ताकि कोई भी अंग अपनी सीमाओं का उल्लंघन न कर सके।

3. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

जैसा कि **मॉन्टेस्क्यू (Montesquieu)** ने अपनी कृति 'द स्पिरिट ऑफ लॉज़' में प्रतिपादित

किया था, शक्तियों का संकेंद्रण तानाशाही को जन्म देता है। संविधानवाद कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे और 'नियंत्रण एवं संतुलन' (Checks and Balances) पर बल देता है।

4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका

संविधानवाद की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। न्यायपालिका न केवल संविधान की व्याख्या करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि विधायी और कार्यकारी कार्य संविधान की सीमाओं के भीतर हों। न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति संविधानवाद का एक प्रमुख उपकरण है।

5. मौलिक अधिकारों का संरक्षण

संविधानवाद व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। किसी भी व्यवस्था को तब तक 'संविधानवादी' नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपने नागरिकों को आधारभूत मानवाधिकार और स्वतंत्रताएँ प्रदान नहीं करती। ये अधिकार सरकार के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा के कवच के रूप में कार्य करते हैं।

6. लोकप्रिय संप्रभुता (Popular Sovereignty)

संविधानवाद इस विचार पर टिका है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। सरकार केवल एक न्यासी (Trustee) के रूप में कार्य करती है, जिसकी वैधता जनता की सहमति पर आधारित होती है।

आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पक्ष

संविधानवाद के दो प्रमुख प्रतिमानों (Models) की चर्चा आवश्यक है:

- **उदारवादी संविधानवाद (Liberal Constitutionalism):** यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धी राजनीति और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। पश्चिमी देशों में इसी मॉडल का बोलबाला है।
- **समाजवादी संविधानवाद (Socialist Constitutionalism):** यहाँ संविधान का उद्देश्य सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय प्राप्त करना होता है। आलोचकों का मानना है कि इस मॉडल में अक्सर राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता है कि 'सीमित शासन' की मूल भावना कमजोर पड़ जाती है।

प्रोफेसर के.सी. व्हेयर के अनुसार, संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है। यह केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि एक 'राजनीतिक संस्कृति' है। यदि किसी समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों

और सहिष्णुता का अभाव है, तो वहां दुनिया का सबसे अच्छा लिखित संविधान भी 'संविधानवाद' को स्थापित करने में विफल हो सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ सत्ता का प्रयोग विधिक सीमाओं और नैतिक मूल्यों के भीतर किया जाता है। यह "मनुष्यों के शासन" के स्थान पर "कानून के शासन" की स्थापना करता है। जैसा कि **थॉमस पेन (Thomas Paine)** ने संकेत दिया था, *"संविधान सरकार का कार्य नहीं, बल्कि सरकार बनाने वाली जनता का कार्य है।"* अतः, संविधानवाद का वास्तविक संरक्षक केवल न्यायालय नहीं, बल्कि एक जागरूक और सजग नागरिक समाज भी है।

Question: Analyze the concept of Constitutionalism and its main features.

Introduction

In simple terms, Constitutionalism is the political philosophy based on 'Limited Government' and 'Rule of Law'. It advocates the idea that the powers of the government should not be unlimited, but should be subject to the boundaries defined by the constitution.

The famous political scientist **Carl J. Friedrich** clarified this by stating that *"Constitutionalism merely means a system for the division of powers and effective control over them."* If a country has a constitution, but the powers of the government are unlimited (like in a dictatorial system), then there may be a 'constitution', but a lack of 'Constitutionalism' will be assumed.

Main Features of Constitutionalism

To understand the nature of Constitutionalism, the analysis of the following points is essential:

1. Rule of Law

The most important pillar of Constitutionalism is the 'Rule of Law'. It means that governance will be carried out not by the whims or wishes of individuals, but through established laws.

- According to the principles of **A.V. Dicey**, every citizen is equal before the law and no person is above the law. Constitutionalism ensures that the rulers themselves are also subject to the same law they implement.

2. Limited and Accountable Government

The fundamental objective of Constitutionalism is to prevent political despotism. It imposes constitutional checks on the powers of the government.

- **K.C. Wheare** argues that Constitutionalism itself means a system of control over the government. In this, the powers of governance are clearly divided so that no branch can violate its boundaries.

3. Separation of Powers

As **Montesquieu** propounded in his work 'The Spirit of Laws', the concentration of powers gives rise to dictatorship. Constitutionalism emphasizes a clear division of powers and 'Checks and Balances' among the executive, legislature, and judiciary.

4. Independent and Impartial Judiciary

The existence of an independent judiciary is essential for the protection of Constitutionalism. The judiciary not only interprets the constitution but also ensures that legislative and executive actions are within the bounds of the constitution. The power of Judicial Review is a major instrument of Constitutionalism.

5. Protection of Fundamental Rights

Constitutionalism prioritizes the dignity and freedom of the individual. No system can be called 'Constitutionalist' until it provides its citizens with basic human rights and freedoms. These rights act as a shield of protection for the individual against the government.

6. Popular Sovereignty

Constitutionalism rests on the idea that the ultimate source of power is the people. The government acts merely as a Trustee, whose legitimacy is based on the consent of the people.

Critical and Analytical Aspect

The discussion of two main paradigms (Models) of Constitutionalism is necessary:

- **Liberal Constitutionalism:** This emphasizes individual liberty, competitive politics, and a market-based economy. This model is dominant in Western countries.
- **Socialist Constitutionalism:** Here, the objective of the constitution is to achieve social equality and economic justice. Critics believe that in this model, the state often becomes so powerful that the original spirit of 'Limited Government' gets weakened.

According to **Professor K.C. Wheare**, Constitutionalism is a dynamic concept. It is not merely a set of rules, but a 'political culture'. If a society lacks democratic values and tolerance, even the world's best written constitution may fail to establish 'Constitutionalism' there.

Conclusion

In conclusion, Constitutionalism is a system of governance where power is exercised within legal limits and moral values. It establishes the "Rule of Law" instead of the "rule of men". As **Thomas Paine** indicated, *"A*

constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government." Therefore, the real protector of Constitutionalism is not just the judiciary, but also an aware and vigilant civil society.